

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड  
पीठासीन अधिकारी : दाताराम आरए.एस

अपील सं. 35/ 2020 (75 एलआर)  
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लि० खानपुर जय सहायक अभियन्ता  
बनाम राजस्थान सरकार  
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00012)

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लि० खानपुर जय सहायक अभियन्ता  
तहसील खानपुर जिला झालावाड

..... अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान  
..... रैस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
विरुद्ध आदेश तहसीलदार खानपुर  
दिनांक 18.03.19 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 149/2019

उपस्थित :

1 अपीलान्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री परवेज अहमद  
निर्णय

दिनांक 09.04.2021

- 2 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार खानपुर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 149/2019 में पस्ति आदेश दिनांक 18.03.2021 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
- 3 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खानपुर के समक्ष 91 राजस्थान भू-राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 149/2019 फटवरे व भू-अभिलेख निरीक्षक खानपुर ने पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट 132 के०वी० ग्रिड सब स्टेशन राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि० द्वारा ग्राम खानपुर की आराजी खसरा नं. 2328 रकब 2.08 बीघा किस गे०मु०तलाई नाजायज कब्जा कर लिया है इसलिये इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही फर्मावे। उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थी को धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 3 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया जिसकी तामील होकर प्रार्थी उपस्थित हुआ तथा अपना पक्ष प्रस्तुत कर अकात करवाया कि ग्राम खानपुर की आराजी खसरा नं. 2328 की 2.08 बीघा भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है बल्कि यह आराजी 132 के०वी० जी०एस०एस०एस०

राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि० खानपुर क्षेत्र रूप से आवंटित हुई है। उक्त आरजी बका राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि० खानपुर द्वारा मान० राजस्व मण्डल अजमेर में अपिल प्रस्तुत की हुई है लेकिन तहसीलदार खानपुर ने दिनांक 18.03.2019 को एक ही दिन में सारे कार्यवही कर अपिलांट के जबब पर कोई विचार किये बिना छपे हुए निर्णय में खाली स्थान को भरकर अपिलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए, एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के अंतर्गत ग्राम खानपुर की आरजी खसरा नं. 2328 रकब 2.08 बीघा किसम गे०मु०तलाई से बेदखल कर लगान 240 का 50 गुना 120 रु. पेनल्टी से दण्डित किये जाने के आदेश पस्ति कर दिया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपिल इस न्यायालय में पेश की है।

- 4 उक्त अपिल दर्ज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर बहस सुनी गई।
- 5 अपिलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री परवेज अहमद ने अपिल मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं फ़ाक्ली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपिलांट्स के जबब पर कोई विचार नहीं किया छपे हुए निर्णय में न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना खाली स्थान भर कर निर्णय कर दिया जो विधि अनुसार नहीं है। ग्राम खानपुर की आरजी ख०न० 2328 की 2.08 बीघा भूमि पर अपिलान्ट का कब्जा नहीं है बल्कि यह आरजी 132 के०वी० जी०एस०एस०एस० राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि० खानपुर क्षेत्र रूप से आवंटित हुई है। जिसके आधार पर विधिका काबिज है। अपिलान्ट द्वारा मान० राजस्व मण्डल अजमेर में विचारधीन अपिल के संबन्ध में निर्णय प्रति दिनांक 10.12.20 प्रस्तुत की गई है जिसमें रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ख०न० 2328 की 4.13 बीघा तक ग्राम खानपुर की किसम के संबन्ध में र्का 1947 के रिकार्ड से संबंधित आवश्यक जांच व राजस्थान सरकार के आदेश के तहत भू रूपन्तरण के आदेश के विरुद्ध किस प्रकार रेफरेन्स पेश की अधिकास्ति प्राप्त है पुनः इस संबन्ध में सुनवाई व विचार कर बाद जांच आवश्यक समझा जावे तो मण्डल के समक्ष पुनः रेफरेन्स पेश किये जाने का निर्णय पस्ति किया गया है।
- 6 वकील अपिलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपंत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।
- 7 इस अपिल में अपिलांट्स ने मुख्य रूप आधार यह लिया है कि अपिलांट के जबब को कंसीडर किये बिना ही निर्णय पस्ति कर दिया है व निर्णय छपे छपये प्ररूप में कर दिया है। अपिलान्ट का ख०न० 2328 की 2.08 बीघा भूमि पर कब्जा नहीं है उक्त भूमि 132 के०वी० जी०एस०एस०एस० राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि० खानपुर क्षेत्र रूप से आवंटित हुई है। जिसके आधार पर विधिका काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय की फ़ाक्ली का एव मान० राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पस्ति निर्णय एव अवलोकन किया गया। मण्डल के निर्णय दिनांक 10.12.20 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त आरजी के संबन्ध में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स किये जाने पर मण्डल के आदेश दिनांक 22.01.2016 से रेफरेन्स स्वीकार कर ख०न० 2328 की 2.08 बीघा राजस्थान विद्युत निगम के नाम से राजस्व रेकर्ड से कम कर भूमि पूर्व अनुसार गे०मु०तलाई दर्ज किये जाने के आदेश

पस्ति किये गये थे पुनः राजस्व मण्डल मे पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर मण्डल के निर्णय दिनांक 10.12.20 से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ख०न० 2328 की 4.13 बीघा वके खानपुर की किस्म के सब्ध मे वर्ष 1947 के रिकार्ड से सबधित आवश्यक जांच व राजस्थान सरकार के आदेश के तहत भू रूपन्तरण के आदेश के विरुद्ध किस प्रकार रेफरेन्स पेश की अधिकास्ति प्राप्त है पुनः इस सबध मे सुनवाई व विचार कर बाद जांच आवश्यक समझा जावे तो मण्डल के समक्ष पुनः रेफरेन्स पेश किये जाने का निर्णय पस्ति किया गया है। अपीलान्ट 132 के०वी० जी०एस०एस०एस० र०र०विद्युत प्रसारण निगम लि० खानपुर के रूप से आवटित हुई है। जिस पर अपीलान्ट विधिका कब्जि है।

- 8 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पस्ति निर्णय में प्रकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की गई है। अपीलांट/अप्रर्षी के जवाब को कंसीडर नहीं किया है और न ही उसे खारिज किया है तथा छपे छपये प्रपत्र में विरोधाभासी तथ्यों युक्त निर्णय पस्ति किया है जो कानूनन उचित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त तहसीलदार खानपुर के निर्णय के पश्चात मण्डल के निर्णय दिनांक 10.12.2020 की पालना में ग्राम खानपुर के ख०न० 2328 की 4.13 बीघा वके खानपुर की किस्म के सब्ध मे वर्ष 1947 के रिकार्ड से सबधित आवश्यक जांच व राजस्थान सरकार के आदेश के तहत भू रूपन्तरण के आदेश के विरुद्ध किस प्रकार रेफरेन्स पेश की अधिकास्ति प्राप्त है इस सबध मे सुनवाई व विचार कर बाद जांच आवश्यक समझा जावे तो पुनः रेफरेन्स पेश करे पस्ति किया गया है जिसमे अतिक्रमण के प्रकरण मे भी इसका प्रभाव संभव है। अतः प्रकरण स्माण्ड योग्य पया जाता है।
- 9 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खानपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.19 निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पटवरी व भू अभिलेख निरीक्षण की साक्ष्य ली जाकर तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 10.12.20 के परिपेक्ष्य मे पुनः विधि अनुसार निर्णय पस्ति करें।

(दातासम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
झालावड़

- 11 निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दातासम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
झालावड़